

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 18 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-291 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

फुटबॉलर मेसी ने अनंत अंबानी का वनतारा देखा...

■ वाइल्डलाइफ सेंटर में आरती की



एजेंसी
गांधीनगर। वर्ल्ड फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने भारत के दौरे के दौरान अनंत अंबानी के वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र वनतारा का भी दौरा किया। इसकी तस्वीरें बुधवार रात जारी की गईं। यहां मेसी ने अनंत और उनकी पत्नी राधिका के साथ आरती की, भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेका। मेसी ने एलिफेंट केयर सेंटर में दो साल पहले बचाई गई बीमार हाथी प्रतिमा के बच्चे मणिक्लाल के साथ फुटबॉल खेला। इस मौके पर अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शावक का नाम लियोनेल भी रखा। उनके साथ उनके क्लब के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल भी मौजूद थे। वनतारा हिलेयर्स के जामनगर स्थित रिफाइनरी परिसर के 3000 एकड़ ग्रीनबेल्ट में फैला हुआ है। वनतारा जानवरों की समर्पित अपनी तरह का देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पूरे इलाके को घने जंगल की तरह विकसित किया गया है। वनतारा में 43 प्रजातियों के 2000 से अधिक जानवर हैं। आज यहां 200 हाथी, 300 से अधिक तेंदुए, बाघ, शेर, जंगुआर, हिरण हैं।

राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे

■ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे



एजेंसी
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय विदेश कांग्रेस (IOC) के कार्यक्रमों ने राहुल का स्वागत किया। राहुल आज बर्लिन में IOC कार्यक्रम में भाग लेंगे। IOC के अनुसार, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मिलकर NRI मुद्दों और पार्टी की विचारधारा फैलाने पर चर्चा करेंगे। राहुल 20 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। उनका जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र (1 से 19 दिसंबर तक) चल रहा है। इसको लेकर भाजपा ने राहुल के जर्मनी दौरे पर निशाना साधा था। राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में यह चौथा विदेश दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वे लंदन, मलेशिया, ब्राजील-कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा था- राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 'LoP' का मतलब 'लीडर ऑफ पर्यटन' होता है। वे लीडर ऑफ पार्टीइंग (पार्टी करने वाले नेता हैं)।

संसद के अंदर ई-सिगरेट पीने का मामला: भाजपा ने जारी किया संसद के अंदर का वीडियो

एजेंसी
नई दिल्ली। सदन के अंदर कथित तौर पर ई-सिगरेट पीने के लिए तुपमूल सांसद के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब इस मामले में भाजपा की ओर से बुधवार को टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट पीने का वीडियो साझा किया गया है। जिसमें वह संसद के अंदर ई-सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिस टीएमसी सांसद पर



भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है, वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद हैं। उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून साफ तौर पर कोई मायने नहीं रखते। जरा हिम्मत तो देखिए, सदन में रहते हुए हथेली में ई-

सिगरेट छिपा रखी थी! भाजपा नेता ने आगे लिखा कि हो सकता है कि धूम्रपान करना गैर-कानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस गलत व्यवहार पर सफाई देनी चाहिए।

दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल बनेंगे एमएच-60आर हेलीकॉप्टर

नौसेना के बेड़े में हुए शामिल

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय नौसेना को जल्द ही बड़ी ताकत मिलने वाली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बहुत जल्द MH-60 रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 ऑप्स को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करेंगे। ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने, समुद्री निगरानी, राहत-बचाव और लड़ाकू अभियानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय नौसेना ने ऐसे कुल 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदने का ऑर्डर दिया है। इन

आधुनिक हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से नौसेना की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता और मजबूत होगी। खास तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ेगी और किसी भी खतरे से निपटने में नौसेना को बड़ी मदद मिलेगी। बता दें कि एमएच 60 आर हेलीकॉप्टर्स एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर हैं। नौसैन्य तौर पर इसे सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में शुमार किया जाता है। समुद्री सीमा की निगरानी करने, मेरीटाइम गतिविधियों पर नजर रखने और पानी के भीतर के खतरों से निपटने में यह हेलीकॉप्टर बेहद अहम है। नौसेना आईएनएस



विक्रांत पर इस हेलीकॉप्टर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करा चुकी है। इसकी मदद से भारत की हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थिति मजबूत हुई है। भारत ने साल 2020 में अमेरिका से लगभग 15,000 करोड़ रुपए में 24

एमएच-60आर हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया था। समुद्री इलाके के लिए इसे दुनिया का सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 834 किलोमीटर है और वजन 689



कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ग्रेप 4 लागू है और सरकारी मजदूरों की मुश्किलों को समझती है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे इस मुश्किल दौर में अपनी आजीविका चला सकें।

किलो है। इसे विमानन क्षेत्र की आधुनिक और चुनौतीपूर्ण नई प्रौद्योगिकियों के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की मौजूदगी का भी पता लगाने में भी माहिर है। ये हेलीकॉप्टर ऐसे समय में भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं जब चीनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के हिंद महासागर में घुसपैठ की रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। एमएच-60आर मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर में निगरानी और हमला करने की कई गुणा अधिक क्षमता इसे खास बनाते हैं।

इथियोपिया की संसद में पीएम मोदी बोले: यह शेरों की धरती

पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इसे पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर

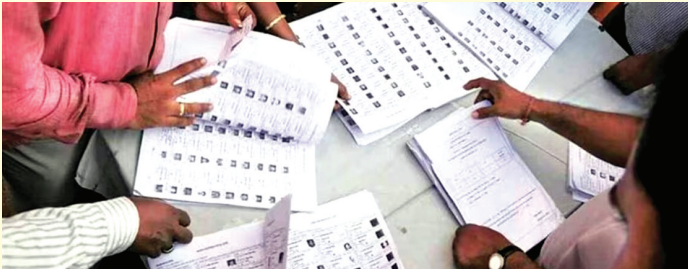
एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह दुनिया की 18वीं संसद है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। मोदी ने कहा कि मुझे इथियोपिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह शेरों की धरती है। यहां मुझे अपने घर जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा गृहराज्य गुजरात भी शेरों की धरती है। इससे पहले इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने मंगलवार को मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। वे द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। मोदी मंगलवार को ही इथियोपिया पहुंचे थे। यह उनका पहला दौरा है। PM अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय



बैठक भी की। इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन खत्म करते ही सांसदों ने मोदी के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। मोदी ने कहा, "कोविड-19 के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाएं और टीके भेजे। इथियोपिया को 40 लाख से अधिक टीके की खुराक की आपूर्ति करना भारत के लिए गर्व की बात थी।" मोदी ने कहा, "भारत में हमने अपना पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यह लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंचने के तरीके में बदलाव लेकर आया है। आज भारत में लगभग हर आदमी पेमेंट, पहचान, सरकारी सुविधा के लिए डिजिटल तरीकों

का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के आधे से ज्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहे हैं। मोदी ने कहा, "भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 5 अरब डॉलर (45 हजार करोड़ रुपए) से अधिक का निवेश किया है। 75,000 से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। हमने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया है।" मोदी ने कहा- भारत और इथियोपिया जलवायु और भावना दोनों में एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं। लगभग 2000 साल पहले, हमारे पूर्वजों ने संबंध स्थापित किए थे। हिंद

महासागर के पार व्यापारी मसालों और सोने का व्यापार करते थे, लेकिन वे केवल वस्तुओं का ही व्यापार नहीं करते थे, वे विचारों और जीवन शैली का भी आदान-प्रदान करते थे। अदीस और धोलेया जैसे बंदरगाह न केवल व्यापार केंद्र थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच सेतु भी थे। आधुनिक समय में, हमारा संबंध एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 1941 में इथियोपिया की मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। पीएम मोदी ने इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे यह सम्मान भारत के लोगों की ओर से स्वीकार करते हैं। इथियोपिया को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका इतिहास इसके पहाड़ों, घाटियों और लोगों के दिलों में जीवित है।



वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा- जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं, उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। इसमें परमानेंट शिफ्ट वोटर्स, डेड वोटर्स,

एम्बेंट और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 58 लाख 20 हजार 898 वोटर्स के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें 24 लाख 16 हजार 852 नाम मृत वोटर्स के हैं। 19 लाख 88 हजार 76 वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं।

इसके अलावा 12 लाख 20 हजार 38 वोटर लापता, 1 लाख 38 हजार 328 डुप्लीकेट या फर्जी, और 57 हजार 604 नाम अन्य कारणों से हटाने के प्रस्ताव में हैं। राज्य के 294 असेंबली एरिया में से सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,553 नाम हटाए गए। यहां से विधायक तुषमूल काग्रेस की नयना बंधोपाध्याय हैं। कोलकाता पोर्ट से कुल 63,730 नाम हटाए गए। इसका प्रतिनिधित्व सीनियर मंत्री फिरोज़ हकीम करते हैं। सबसे कम नाम बांकुरा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए। यहां 5,678 नाम हटाए गए। गोवा-11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख ने फॉर्म जमा किए।

ऋषिकेश में एक्सयूवी ट्रक में घुसी, 4 दोस्तों की हुई मौत

■ 120 की स्पीड, शव सीट से चिपके



एजेंसी
ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज रफ्तार महिंद्रा XUV500 कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकराकर उसके नीचे घुस गई, जिससे मौके पर ही कार में सवार 4 दोस्तों की मौत हो गई। इनमें से एक की पत्नी प्रेमेन्त है। कार हरिद्वार की ओर से आ रही थी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। घटना से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कार इतनी स्पीड में थी कि सड़क पर चल रही एक गाय भी अनबलेंस हो गई। इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली ऋषिकेश के मुताबिक, 16 दिसंबर की रात

ऋषिकेश कंट्रोल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि पीएनबी सिटी गेट के पास एक कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी है। सूचना मिलते ही कोतवाली ऋषिकेश, श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल चौकी से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। गाड़ी का नंबर UK 07FS 5587 और ट्रक का नंबर HR 58 A 9751 था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मांस के टुकड़े सड़क पर इधर-उधर बिखर गए थे। पुलिस ने मुताबिक, हादसा मनसा देवी मंदिर के रेलवे फाटक के पास हुआ। क्षत-विक्षत शव बाहर निकालने के लिए पुलिस को भारी मेहनत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मांस के टुकड़े सड़क पर इधर-उधर बिखर गए थे।

खड़गे बोले: नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ बदले के लिए

गांधी परिवार को सताया जा रहा, कोर्ट का फैसला मोदी-शाह के मुंह पर थपड़

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा- नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। खड़गे ने कहा- नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन ये लोग (भाजपा) CBI और ED जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी परिवार को सताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा- इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई। किसी की शिकायत मात्र से जांच शुरू कर दी। हमारा नारा है, सत्यमेव जयते। कल कोर्ट का फैसला न्याय के हित में आया है। कोर्ट का फैसला PM नरेंद्र मोदी और शाह के मुंह पर थपड़ जैसा है। दिल्ली के कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एऊ की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ED चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी अखड़ की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। CBI ने सालों तक



FIR दर्ज नहीं की। ED भी लंबे समय ECIR दर्ज करने से बचती रही। फिर ED ने FIR के बिना ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ED ने प्रक्रिया उलट दी। पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और बाद में FIR कराई। PMLA में पहले अपराध की जांच और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होती है। ED को CBI की तरह इंतजार करना चाहिए था। PMLA विशेष कानून है, इसे सामान्य आपराधिक कानून के प्रावधानों से विस्तारित नहीं कर सकते। प्रोसीडर ऑफ क्राइम तभी लागू होगा, जब आपराधिक गतिविधि का कानूनी अस्तित्व हो। FIR जांच प्रक्रिया की बुनियाद होती है। निजी शिकायत इस स्तर की जांच का जिक्र नहीं करती। निजी शिकायतकर्ता ED जैसी एजेंसी के साथ नोडल ऑफिसर की तरह समन्वय नहीं कर सकता। BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस के ही

मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक, कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड अगिंगाईजेशन नाम की संस्था बनाई, जिसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली AJL का अवैध अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ये सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। आरोप है मुताबिक, 2000 करोड़ रुपये की कंपनी को केवल 50 लाख रुपये में खरीदा गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज की अब मौत हो चुकी है।

आपराधिक मामलों के निपटान में देरी अन्याय जैसा

डॉ. के.पी. सिंह

एक दिवंगत रेलवे टीटीई को 50 रुपये की रिश्ततखोरी के आरोप से मुक्त होने में 40 साल लग गए, जिसके कारण अपने जीवन-काल में उन्हें सरकारी नौकरी, सम्मान और मानसिक शांति खोने का दश झेलना पड़ा था। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन में तैनात लिपिक, जागेश्वर प्रसाद अवधिया को 100 रुपये रिश्तत लेने के आरोप में गिरफ्तारी के 39 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2005 और 2006 के सबसे चौकाने वाले निठारी सीरियल किलिंग मामलों में नवम्बर, 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेन्द्र कोली और पंडेर को भी दोषमुक्त कर दिया है। वस्तुतः भारत में आपराधिक मामलों के निर्णय में देरी आपराधिक न्याय प्रणाली में अन्तर्निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किए गए सभी लोगों में से 46 प्रतिशत से अधिक को विचाराधीन कैदियों के रूप में विभिन्न अवधियों के लिए जेलों में सजायापता दोषियों की तरह कष्ट सहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का एजेंडा तय करना प्रशंसनीय पहल है।

29 अक्तूबर, 2025 को भी आरोप निर्धारण में अत्यधिक देरी पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी और इस समस्या के समाधान के लिए समुचित दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु भारत के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल से सहयोग मांगा था। अपराधिक मामलों के निपटान में देरी महज आकस्मिक नहीं, जिसे दिशा-निर्देश बनाकर रोका जा सके, वास्तव में यह उभरती दरपेश परिस्थितियों से निपटने में संस्थानगत विफलता का मामला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रकाशन ‘भारत में अपराध-2023’ के अनुसार, पिछले वर्ष के लम्बित 2,45,84,673 मामलों में इस वर्ष 8,25,681 और आपराधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2023 के अन्त तक देश में कुल 2,54,10,354 आपराधिक मामले निचली अदालतों में लम्बित हो गए। इस वर्ष न्यायालयों द्वारा 40,95,080 आपराधिक मामलों का ही निपटान सम्भव हो सका जबकि इस दौरान 49,20,771 नए मामले निर्णय के लिए अदालतों में प्राप्त हुए। इस प्रकार लम्बित मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 16 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। लम्बित आपराधिक मुकदमों के पीछे के कारणों को समझने के लिए गहन विश्लेषण और शोध की

आवश्यकता है। इस बढ़ते रुझान को रोकने और लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है। इस रणनीति में निम्नलिखित आयाम शामिल किए जा सकते हैं -

पहला, इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है कि एक पुलिस थाना क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक ही ट्रायल कोर्ट हो सकता है। लम्बित मुकदमों की संख्या के आधार पर एक थाना क्षेत्र में एक से अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक ट्रायल कोर्ट में दांचागत सुविधाओं के साथ-साथ कम से कम तीन रेटेनोग्राफर और दो लोक अभियोजकों की तेनाती का प्रावधान हो। जब तक नियमित पीठासीन अधिकारियों, अभियोजकों, सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती और अदालत कक्ष नहीं बन जाते, तब तक जिला जज को अदालतों के लिए भवन किए गए पर लेने के लिए और अस्थायी अदालतों के संचालन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा सकता है।

दूसरा, कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में एक ही न्यायाधीश आपराधिक और सिविल दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि क्षेत्राधिकार विभाजित कर दिया जाए और विभिन्न प्रकृति के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेट/सिविल जज नियुक्त कर दिए जाएं तो इससे मुकदमों का शीघ्र निपटान सम्भव होगा। कुछ राज्यों में यह प्रथा लागू भी है।

तीसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 359 में संशोधन करके ‘समझौता योग्य मामलों’ की सूची में विस्तार किया जा सकता है और 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय सभी अपराधों को समझौता योग्य अपराध घोषित करके उनका ‘शीघ्र निपटान’ सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत में अपराध, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में केवल 3,03,802 छोटे आपराधिक मामलों में ही पक्षकारों द्वारा समझौता किया गया जो कुल पंजीकृत मामलों का लगभग एक प्रतिशत है।

चौथा, बीएनएसएस में प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध और सामाजिक-आर्थिक अपराधों संबंधी मामलों को छोड़कर बाकी सभी अपराधों में जहां 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, पक्षकार आपसी सहमति से मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं जिसे ‘प्ली-बार्गेनिंग’ की संज्ञा दी गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में केवल



42,318 मामलों का ही प्ली-बार्गेनिंग के माध्यम से निपटान किया जा सका था। इस प्रावधान में कुछ कमियां हैं। प्ली-बार्गेनिंग के सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन करके प्ली-बार्गेनिंग करने वाले अपराधी के सिर से अपराधी का टैग हटाया जा सकता है। अमेरिका में पहले से ही ही ऐसा प्रावधान है। इसके अलावा, पक्षकारों को यह भी छूट हो कि आपराधिक कार्यवाही के प्रत्येक चरण में वे प्ली-बार्गेनिंग की प्रक्रिया अपनपाकर अपने मुकदमों का फैसला करवा सकें।

पांचवां, आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने को बीएनएसएस में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें समयबद्ध आरोप तय करना, अदालत में गवाही के लिए विशेषज्ञों को बुलाने की गुंजाइश सीमित करना, पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से फेसले अपलोड करना, मुकदमों से पहले केस सम्पत्तियों का निपटान, रिमांड और साक्ष्य दर्ज करने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का प्रयोग और 3 वर्ष तक की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए ‘सम्परी ट्रायल’ द्वारा सुनवाई का दायरा बढ़ाना शामिल है। इन कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से प्रयोग सुनिश्चित करने और उनकी निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है।

छठा, पर्याप्त संख्या में अभियोजकों, आशुलिपिकों और

लिपिकों के न होने और अदालतों के काम के बोझ में दबे होने के कारण अनेक बार अदालतों में बुलाए गए गवाहों से दिन के समाप्त हो जाने तक पूछताछ नहीं हो पाती है। इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सातवां, रिक्तियों की पूर्ति हेतु न्यायाधीशों, अभियोजकों और अदालती कर्मचारियों की वार्षिक आधार पर नियमित भर्तियां की जानी चाहिए और सम्बन्धित हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

आठवां, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 18 हजार से अधिक और हाईकोर्टों में 63 हजार से अधिक आपराधिक मामले लम्बित हैं। इन अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा रिक्तियों को भरने के अलावा इन लम्बित मामलों को कम करने का अन्य कोई उपाय प्रतीत नहीं होता है।

ब्रिटिश राजनेता विलियम इवाट ग्लेडस्टोन ने कहा था ‘न्याय में देरी न्याय से इंकार करने के समान है।’ एक कल्याणकारी राज्य अपने लोगों को समय पर न्याय से वंचित नहीं कर सकता, वरना विकास प्रक्रिया अराजकता का शिकार हो जाएगी। सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को गम्भीरता से लेकर न्याय देने में हो रही देरी को रोकने के अभियान में स्वेच्छा से भागीदार बनना चाहिए।

लेखक हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।

संपादकीय

अमीरी दे गरीब को त्रास

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घातक पर्यावरण संकट झेल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट के निदान के लिये जो उपाय लागू किए जा रहे हैं, उसका खमियाजा गरीबों को झेलना पड़ रहा है। इस संकट की संवेदनशीलता को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवन शैली से उपजी मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। दरअसल, बिगड़ते प्रदूषण संकट के बावत दायर याचिकाओं को आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह इस बावत प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगा। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए ये टिप्पणी की थी। अदालत का कहना था कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-4 लागू करने के चलते जो पाबंदियां लागू की गई हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को हो रहा है। इससे निर्माण कार्य बंद होने से हजारों गरीब मजदूरों का चूल्हा नहीं जल सकेगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस बावत कहा कि संपन्न लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही कहा कि हमें समस्या का पता है और इसलिए हम ऐसे आदेश पारित करेंगे, जिनका पालन किया जा सकेगा। कहा कि कुछ निर्देश ऐसे भी हैं, जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर-गरीब पर समान असर पड़ता है। निस्संदेह, देश की शीर्ष अदालत ने देश व समाज की दुखती रग पर ही राय रखी है। महानगरों में अमीर तबके की विलासिता के चलते ही पर्यावरण व अन्य संकटों को बढ़ावा मिलता है। महानगरों में लगातार सड़कों का विस्तारीकरण, नए हाइवे निर्माण व ओवर ब्रिज निर्माण के बावजूद जाम व प्रदूषण का संकट कम नहीं हो रहा है। दरअसल, हमने अपनी सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यापक सामाजिक हितों की अनदेखी की है। आमतौर पर एक अकेले व्यक्ति के लिये कारें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। जो न केवल सड़कों में ज्यादा जगह घेरती है, बल्कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके प्रदूषण को भी बढ़ावा देती हैं। यही वजह है कि आम आदमी सरकार ने अपने कार्यकाल में ऑड-इवन प्रणाली शुरू करने को प्राथमिकता दी थी ताकि सड़कों पर कारों का सैलाब कम किया जा सके। तब बात उठी थी कि एक दिशा में और एक ऑफिस की तरफ जाने वाले लोग कार शेरार करके चले। विडंबना यह है कि सताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में एसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं।

(लेखक- ललित गर्ग)

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज जिस घातक पर्यावरण संकट से गुजर रही है, वह केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिये चेतावनी है। विडंबना यह है कि इस संकट के नाम पर जो तात्कालिक उपाय लागू किए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा खमियाजा वही तबका भुगतता है, जिसकी इसमें सबसे कम भूमिका होती है-गरीब और श्रमिक वर्ग। इसी पीड़ा को शब्द देते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवनशैली से पैदा हुई मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। यह टिप्पणी न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और नैतिक चेतना को झकझोरने वाली भी है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागवी और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि ग्रेप-4 जैसी सख्त पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। निर्माण कार्य रुकते हैं, दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी टप हो जाती है, जबकि प्रदूषण पैदा करने वाली जीवनशैली में शामिल संपन्न तबके पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या की जड़ अमीरों की जीवनशैली है और समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत ऐसे प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सख्ती से लागू भी किया जा सकेगा।

जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा, अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल ढालना होगा एवं प्रकृति-एवं पर्यावरण के



अनुशासन का पाठ

गुरु अंबुजानंद के पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उनका आश्रम लंबे समय से चल रहा था। अब चूंकि अंबुजानंद काफ़ी वृद्ध हो गए थे, गुरुकुल चलाना उनके लिए कठिन हो रहा था। वह अपने शिष्यों में से ही किसी एक को गुरुकुल का सारा कार्यभार सौंपना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने 18 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, आप सभी प्रतिभाशाली, मेहनती और ईमानदार हैं। यदि मैं आपको शिक्षा के लिए किसी विशेष क्षेत्र में नियुक्त करना चाहूँ तो आप कौन-कौन से क्षेत्र को चुनना चाहेंगे? यह सुनकर सभी शिष्य कुछ देर सोचते रहे और फिर 17

विद्यार्थियों ने अपने-अपने मनपसंद क्षेत्रों के नाम गुरु को बता दिए। अठारहवां शिष्य आयुष अभी तक कुछ सोच ही रहा था। उसे चुप देखकर गुरु ने पूछा, बेटा आयुष, तुमने अपने लिए किसी क्षेत्र का चुनाव नहीं किया? गुरु की बात सुनकर आयुष ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैंने आपसे ही शिक्षा ग्रहण की है। मैं आपके द्वारा सीखी गई शिक्षा को जन-जन तक फैलाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे किसी क्षेत्र विशेष का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर क्षेत्र में आपके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहूँगा।

हालांकि क्षेत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके

दिए गए मूल्य या संस्कार का प्रसार, जो शास्त्रों से अलग है। मैं चाहता हूँ कि लोग उसे जानें ताकि वे नैतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ हों। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है।

आपने जो अनुशासन का पाठ हमें पढ़ाया है, उसे तो मैं विशेष रूप से सिखाना चाहूँगा। ज्ञान पाने के लिए व्यक्तित्व को एक खास सांचे में ढालना पड़ता है। आपने जिस तरह हमें ढाला है, मैं भी दूसरों को ढालना चाहूँगा। आयुष की बात सुनकर गुरु अंबुजानंद का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, आज से यह गुरुकुल तुम्हारी देखरेख में ही चलेगा।

हटाए गए और जो नोटिस जारी किए गए दोनों ही अवैधानिक कृत्य हैं। चुनाव आयोग की यह कार्यवाही चुनाव आयोग की जवाबदेही, आयोग की पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। केंद्रीय चुनाव आयोग यह नहीं बता पा रहा है, कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, उनके नाम क्यों काटे गए। ऐसी स्थिति में आम मतदाता कैसे मतदान के अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे।

चुनाव आयोग के आयुक्तों और शीर्ष अधिकारियों के बयान और जमीनी हकीकत के बीच विरोधाभास साफ दिखाई दे रहा है। संविधान में उल्लेखित नियम और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता के खिलाफ शिकायत और जांच के पश्चात ही आयोग किसी का नाम जोड़ या घटा सकता है। चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान लेकर किसी भी मतदाता का नाम हटाने का अधिकार नहीं है।

एसआईआर में चुनाव आयोग ने अवैधानिक रूप से काटे लाखों नाम?

विचारमंथन

(लेखक-सनत जैन)

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया मानी जाती है। इसी प्रक्रिया में सभी संवैधानिक अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास हैं। संविधान ने व्यापक अधिकार और जिम्मेदारियाँ चुनाव आयोग को सौंपी हैं। इसके लिए संविधान में अधिकार और चुनाव आयोग ने नियम बना रखे हैं। बिहार में वोटरलिस्ट की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने ना तो संविधान के प्रावधान को माना, ना ही अपने नियमों को माना। हालिया खुलासों ने चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में संविधान कानून और नियमों की अनदेखी की गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो कार्यवाही और

प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको लेकर चुनाव की निष्पक्षता तथा चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो संकेत मिले हैं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे चिंताजनक स्थिति है। संविधान एवं चुनाव आयोग का कानून स्पष्ट रूप से कहता है। किसी भी मतदाता की पात्रता पर संदेह होने की स्थिति में नोटिस जारी करने का अधिकार केवल स्थानीय चुनाव अधिकारी (ईआरओ) के पास है। बिहार की एसआईआर में लाखों नोटिस, सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पोर्टल में वोटर के नाम पर डाले गए हैं, जबकि इसकी ईआरओ को कोई जानकारी नहीं थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वह काम किया है, जिसका उसके पास अधिकार ही नहीं था। केंद्रीय चुनाव आयोग का यह कृत्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता मतदाताओं के मतदान के अधिकार खत्म करने और लोकतंत्र में मतदाताओं और राजनीतिक दलों के अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात घालना है। चुनाव आयोग ने

विकेंद्रीकृत चुनाव प्रक्रिया का केंद्रीकरण कर एक तरह से मनमानी की है और संविधान एवं कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। संविधान ने नागरिकों के मतदान अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। स्थानीय अधिकारियों के पास जो संवैधानिक अधिकार दिए गए थे उसे अवैध रूप से छीनने का काम भी चुनाव आयोग ने किया है। जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है।

इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू यह है, नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद थे। जिन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा किए थे। सभी नोटिसों में एक तरह की आपत्ति एवं कारण लिखे गये। लाखों मतदाताओं के लिए एक समान वजह होना संभव ही नहीं था। चुनाव आयोग में जमा किए गए जो दस्तावेज नोटिस में अथुंर या नाकाफी बताए गए थे, उन नोटिसों पर तारीख तय दर्ज नहीं थी।

यह पूरी प्रक्रिया घोर लापरवाही और गैर कानूनी थी। यह खुलासा इस बात का सबूत है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी अधिकार अपने पास ले लिए हैं। जिसके कारण स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अधिकारों का उपयोग भी चुनाव आयोग दिल्ली में बैठे-बैठे कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग का स्थानीय चुनाव अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई सुनियोजित दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है। जो आंकड़े और प्रक्रिया सामने आई है, वह चिंताजनक है। बिहार में एसआईआर के दौरान 68 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, जिसके कारण वह मतदान नहीं कर पाए। मतदान का मौलिक अधिकार चुनाव आयोग द्वारा अवैधानिक रूप से खत्म कर दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग के पोर्टल से जो नोटिस जारी हुए थे। उसमें से करीब 10 हजार मामलों में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कारण भी नहीं बताया। इससे स्पष्ट है कि जो नाम

टाटा केमिकल्स ने एनसीडी के माध्यम से 1,500 करोड़ जुटाए

नई दिल्ली टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने निजी निर्गम के जरिए गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) जारी कर 1,500 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी ने बताया कि यह एनसीडी असुरक्षित, सूचीबद्ध और कर योग्य है। कंपनी ने 1,00,000 रुपए अंकित मूल्य वाले 1,50,000 एनसीडी जारी किए। इनकी अवधि 2 वर्ष 364 दिन है और कूपन दर 7.06 फीसदी तय की गई है। ये एनसीडी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऋण खंड में सूचीबद्ध होंगे। एनसीडी निवेशकों को निश्चित और स्थिर रिटर्न देते हैं, जबकि कंपनी के लिए यह दीर्घकालिक फंड जुटाने का आसान साधन है। आवंटन को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित आंतरिक समिति ने मंजूरी दी।

रिलायंस कंज्यूमर ने 75 साल पुराने एसआईएल ब्रांड किया रीलॉन्च

बेंगलुरु रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीसीएल)ने 75 साल पुराने फूड ब्रांड एसआईएल को नए रूप में बाजार में पेश किया है। कंपनी ने एसआईएल के तहत नूडल्स, केचप और जैम जैसी प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की है। एसआईएल नूडल्स चार वैरिएंट्स-मसाला, आटा विद वेजीज, कोरियन के-फायर और चाउ-चाउ-5 रुपए से शुरू होंगे। एसआईएल केचप असली टमाटो से तैयार, बिना कृत्रिम रंग या सिंथेटिक सामग्री, कीमत 1 रुपए और एसआईएल मिक्स्ट फूट जैम आठ फलों से बनी, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम पैक में उपलब्ध, शुरुआती कीमत 22 रुपए है।

जापान का निर्यात नवंबर में सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़ा

आयात केवल 1.3 फीसदी की वृद्धि हुई
बैंकाक जापान के निर्यात में नवंबर में सालाना आधार पर 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आयात केवल 1.3 फीसदी बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप देश का कुल व्यापार अधिशेष 322.2 अरब येन (लगभग 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। अमेरिका को निर्यात में लगभग 9 फीसदी की वृद्धि हुई। कार, रसायन और कैमरा निर्यात ने मशीनरी और इस्पात में गिरावट की भरपाई की। अमेरिका से आयात लगभग तीन गुना बढ़ गया, मुख्य रूप से तेल, अनाज और अन्य खाद्य उत्पाद। इसके कारण जापान का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बढ़कर 739.8 अरब येन (4.7 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया, जो एक साल पहले की तुलना में 11 फीसदी अधिक है। यूरोपीय संघ को निर्यात में लगभग 20 फीसदी की वृद्धि हुई। मुख्य कारण मशीनरी, वाहन और अन्य विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग रही।

एटर्नल के शेयर में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली फूड डिलीवरी और क्लिक कॉमर्स कंपनी एटर्नल के शेयर में मंगलवार को इंट्रा-डे कारोबार के दौरान करीब 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। शेयर 285.70 रुपये तक गिर गया, जो पिछले सात महीनों में एक दिन की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। इससे पहले 2 मई 2025 को 5.3 और 7 अक्टू 2025 को लगभग 10 फीसदी की गिरावट आई थी। 16 अक्टूबर 2025 को शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 368.40 रुपये पर था, जो लगभग 23 फीसदी है। बाजार में इस गिरावट की प्रमुख वजह सरकार द्वारा चार नए श्रम कानूनों को 21 नवंबर 2025 से लागू करने का निर्णय माना जा रहा है। ये कानून 2020 में पारित हुए थे लेकिन अब तक लागू नहीं हुए। नए नियमों के तहत गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान और न्यूनतम वेतन तय करना अनिवार्य होगा।

वैश्विक व्यापार में शुल्क का हथियार के रूप में बढ़ता प्रयोग, भारत सतर्क रहे: वित्त मंत्री

केवल शुल्क से निपटना पर्याप्त नहीं है; भारत को अपनी आर्थिक मजबूती के बल पर लाभ लेना चाहिए

नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्तमान में वैश्विक व्यापार स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गया है। उन्होंने बुधवार को आयो जित भारत तो र्थिक सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि कई देश शुल्क और अन्य उपायों का उपयोग व्यापार को हथियार बनाने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना था कि केवल शुल्क के जरिए स्थिति को संभालना पर्याप्त नहीं है। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी शुल्क

का इस्तेमाल आक्रामक हथियार के रूप में नहीं किया। भारत का उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है, ताकि वे सस्ते या अत्यधिक माल से प्रभावित न हों। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक मजबूती ही भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अतिरिक्त लाभ दे सकती है। मंत्री ने अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क और मैक्सिको की नई घोषणा का उदाहरण दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ देश अपने हितों के लिए शुल्क का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि शुल्क

वनस्पति तेल आयात में भारी गिरावट, रिफाईंड पामोलीन अधिक प्रभावित

नवंबर में कुल 11.83 लाख टन वनस्पति तेलों का आयात हुआ

नई दिल्ली
तेल वर्ष 2025-26 की शुरुआत (नवंबर 2025) भारत में वनस्पति तेल आयात के लिहाज से कमजोर रही। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में कुल 11.83 लाख टन वनस्पति तेलों का आयात हुआ। इसमें करीब 11.50 लाख टन खाद्य तेल और 33 हजार टन गैर-खाद्य तेल शामिल

थे। यह पिछले वर्ष के समान महीने में 16.50 लाख टन आयात के मुकाबले लगभग 28 प्रतिशत कम है। अक्टूबर 2025 में आयात 13.32 लाख टन था, जबकि नवंबर में यह 11.83 लाख टन रह गया, यानी मासिक आधार पर लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट। रिफाईंड पामोलीन (आरबीडी पामो लिन) का आयात सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। नवंबर में केवल 3,500 टन आयात हुआ, जबकि पिछले साल



उचित नहीं हैं, लेकिन अब नए तरीके से शुल्क बाधाएँ बनाना आम हो गया है। सीतारमण ने व्यापारिक बातचीत में भारत को सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया।

उनका मानना है कि सिर्फ शुल्क नीति पर्याप्त नहीं है, बल्कि मजबूत आर्थिक स्थिति और सतर्क कूटनीति ही भारत को वैश्विक व्यापार में सुरक्षित और लाभकारी बनाएगी।



यह 2.85 लाख टन था। विशेषज्ञों का मानना है कि कूड पाम तेल और आरबीडी पामोलीन के बीच बढ़े आयात शुल्क अंतर (8.25 से 19.25 फीसदी मई 2025 से) का सीधा असर पड़ा। जुलाई से ही इसके आयात में गिरावट देखी जा रही थी, जो नवंबर में और स्पष्ट हो गई। कच्चे सोया तेल का आयात 3.70 लाख

टन पर आ गया, सालाना 9 प्रतिशत कम। कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात लगभग 1.43 लाख टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 58 प्रतिशत कम है।

ईलॉन मस्क की दौलत 600 अरब डॉलर के पार, बेजोस और ज़ुकरबर्ग को पछाड़ा

► **स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्सएआई ने बढ़ाई मस्क की नेटवर्थ**
नई दिल्ली
टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक ईलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने

हुए हैं। फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति बढ़कर करीब 684.2 अरब डॉलर पहुंच गई। हाल के दिनों में उनकी नेटवर्थ में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है, जिसका सबसे बड़ा कारण उनकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स की तेजी से बढ़ती वैल्यू मानी जा रही है।

महज दो दिनों में उनकी कुल संपत्ति ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी निजी कंपनियों की

वैल्यूएशन में आए बदलाव के कारण हुई है। मस्क की संपत्ति बढ़ने की सबसे बड़ी वजह स्पेसएक्स है। रिपोटर्स के अनुसार स्पेसएक्स अगले साल शेंयर बाजार में उतर सकती है और इसकी वैल्यू करीब 800 अरब डॉलर आंकी जा रही है। ईलॉन मस्क की कंपनी में लगभग 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे उनकी निजी संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया है। ईलॉन मस्क की कुल संपत्ति अब कई बड़े अरबपतियों की संयुक्त दौलत से

भी ज्यादा बताई जा रही है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग और एनबीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग तीनों की कुल संपत्ति मिलाकर भी मस्क की दौलत से कम बताई जा रही है। ईलॉन मस्क के बाद अल्फाबेट के को-फाउंडर लैरी पेज करीब 252 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लैरी एलिसन 239.8 अरब डॉलर के साथ तीसरे, जबकि जेफ बेजोस 235.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं।

शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद

मुंबई
भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 120.21 अंक टूटकर 84,559.65 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 41.55 अंक नीचे आकर 25,818.55 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान रियल्टी शेयरों के कारण बाजार पर दबाव पड़ा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.84 फीसदी नीचे आकर बंद हुआ। निफ्टी फाइनेशियल सर्विसेज 0.49 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 0.47 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.44 फीसदी नीचे आकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक 1.29 फीसदी, निफ्टी आईटी 0.29 फीसदी और निफ्टी मेटल 0.25 फीसदी फिसलकर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान लार्जकैप की जगह पर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अधिक बिकवाली रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 321.95 अंक नीचे आकर 59,388.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 126.60 अंक टूटकर 17,138.55 पर रहा था। सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, सनफार्मा, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टीसीएस, टाटा



स्टील, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल के शेयर लाभ में रहे जबकि ट्रेट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, बीईएल, टाइटन, एशियन पेट्रॉस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरे। इससे पहले आज सुबह बाजार लगभग सपाट रुख के साथ खुले। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार जारी कमजोरी ने निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक असर डाला। सेंसेक्स 84,856 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 169.35 अंक की बढ़त के साथ 84,849.21 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं निफ्टी भी

25,902 अंक पर सपाट खुलने के बाद यह 54.15 अंक की मजबूती के साथ 25,920 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों में बुधवार को ज्यादातर कमजोरी देखने को मिली। जापान से आए नए व्यापार आंकड़ों के बाद निक्केई 225 में 0.14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी, एएसएसए 200 भी 0.21 फीसदी गिरावट, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी क्षेत्रीय रूझान के उलट 0.5 फीसदी उछला। अमेरिकी बाजारों में भी मिला-जुला रुख रहा। एसएंडपी गिरावट के साथ 0.24 फीसदी नीचे बंद हुआ। नैसडेक कंपोजिट 0.23 फीसदी बढ़ा, जबकि डॉव जोस 0.62फीसदीगिरा।

सरकार करेगी इंडियन ओवरसीज बैंक के तीन फीसदी शेयरों का विनिवेश

गैर-खुदरा निवेशकों के लिए सार्वजनिक बिक्री प्रारंभ
नई दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की सार्वजनिक बिक्री (ओएफएस) गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बुधवार से शुरू हो गई है। सरकार अपनी तीन फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके तहत 2 फीसदी हिस्सेदारी यानी 38.51 करोड़ शेयर मूल पेशकश में बेचे जाएंगे, जबकि 1 फीसदी हिस्सेदारी यानी 19.25 करोड़ शेयर 'ग्रीन शू' विकल्प के तहत बेचे जा सकते हैं। इस कदम से सरकार लगभग 1,960 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रही है। खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस गुरुवार से खुलेगा। प्रत्येक शेयर का न्यूनतम मूल्य 34 रुपए तय किया गया है। मंगलवार को आईओबी का शेयर बाजार में 36.57 रुपए पर बंद हुआ था। ओएफएस में 1.5 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पात्र कर्मचारी अधिकतम 5 लाख रुपए तक के शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारियों को बैंक की हिस्सेदारी में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर देती है। इंडियन ओवरसीज बैंक में वर्तमान में सरकार की हिस्सेदारी 94.61 फीसदी है। यह विनिवेश न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम के अनुरूप किया जा रहा है, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम जनता के पास होनी चाहिए।

30 हजार यूनिट्स बिक चुकी नई एसयूवी विक्टोरिस की



नई दिल्ली
महज तीन महीनों में ही मारुति सुजुकी की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस की 30 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो इस सेगमेंट में इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। खास बात यह है कि गैड विटारा के प्लेटफॉर्म पर बनी होने के बावजूद विक्टोरिस ने बिक्री के मामले में उसी को पीछे छोड़ दिया है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, अडवा लेवल-2, 360 डिग्री कैमरा और 5-स्टार भारत एनकेप रेटिंग दी गई है। इन्हीं खूबियों के चलते विक्टोरिस तेजी से ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है। ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, ऑटोमैटिक और ई-सीवीटी के विकल्प दिए गए हैं, वहीं ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है। डिजाइन के मामले में विक्टोरिस नई और मॉडर्न नजर आती है। इसका एक्सटीरियर बोल्ड है, जबकि इंटीरियर पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दूसरा 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग

बड़े पैमाने पर रद्दीकरण शुरू हो गए। दिसंबर के पहले कुछ दिनों में देशभर के एयरपोर्ट्स पर 5,500 से ज्यादा इंडिगो उड़ानें रद्द हुईं, जिससे 6 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। इसे भारत के कूप्रबंधन का सबसे बड़ा घरेलू विमानन संकट माना जा रहा है। इसके बाद सरकार और एयरलाइन के बीच दोषारोपण शुरू हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने डीजीसीए का बचाव करते हुए संकट के लिए इंडिगो के कूप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यात्रियों को पूरा रिफंड देने के निर्देश दिए और चार-सदस्यीय समिति से जांच कराने की घोषणा की। विशेषज्ञों के अनुसार इंडिगो ने सर्दियों के शूट्यूटल में आक्रामक विस्तार किया। उसे घरेलू उड़ानों में पिछले सर्दियों की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक अनुमति मिली, जबकि अन्य एयरलाइनों ने क्षमता घटाई। यही असंतुलन इस बड़े संकट की मुख्य वजह बना।

इंडिगो संकट: कुप्रबंधन, नए नियम और ठप हुआ देश का विमानन नेटवर्क

► **नवंबर महीने में ही इंडिगो ने 950 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं**

नई दिल्ली
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में आया विमानन संकट अचानक नहीं था, बल्कि इसके संकेत नवंबर में ही दिखने लगे थे। 1 नवंबर से पायलटों के लिए अधिक आराम समय से जुड़े नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम लागू होने के बाद नवंबर महीने में ही इंडिगो ने 950 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं। इसके बावजूद एयरलाइन ने न तो स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और न ही यात्रियों के लिए कोई ठोस वैकल्पिक योजना बनाई। 1 दिसंबर को इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के शीर्ष अधिकारियों से नए नियमों पर स्पष्टता के लिए मुलाकात की। इस बैठक में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि एयरलाइन गंभीर परिचालन संकट की ओर बढ़ रही है। दो दिन बाद ही 65 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की उड़ानों की



जहां कभी तबाही मचाई थी चट्टानों ने वहीं आज उभरी आस्था, जानें 31 दिव्य आकृतियों का रहस्य



2013 में केदारनाथ घाटी पर आई भीषण त्रासदी ने पूरे देश को हिला दिया था। उस दौरान पहाड़ टूटे, विशाल चट्टानें बहकर मंदिर के पास आकर रुक गईं और हजारों लोगों की जान बचाने में ढाल बनीं। आज वही चट्टानें एक नए आस्था केन्द्र के रूप में लोगों का ध्यान खींच रही हैं। चट्टानों पर दिखी 31 रहस्यमयी आकृतियां स्थानीय लोगों, पुजारियों और कई विशेषज्ञों के अनुसार, इन चट्टानों की सतह पर करीब 31 अलग-अलग आकृतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। इनमें भगवान शिव से मिलती-जुलती आकृतियां, नंदी के जैसे आकार, साधु-संतों की आकृतियां जैसी रेखाएं भक्तों के रूप में दिखने वाली उभरी रूप-रेखाएं दूर से ये आकृतियां साधारण सा पत्थर ही लगती हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर इनके आकार बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से कई लोग इन्हें प्राकृतिक मूर्ति परिसर जैसा मानने लगे हैं।

क्या यह प्रकृति का चमत्कार या दिव्य संकेत? अब तक वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऐसी विशाल और गहरी आकृतियां चट्टानों पर कैसे बनीं। कुछ विशेषज्ञ इन्हें प्राकृतिक भू-आकृतिक संरचना बताते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसे शिव की उपस्थिति और दिव्य संकेत मान रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है- ‘2013 की आपदा के बाद भी मंदिर सुरक्षित रहा... अब इन चट्टानों में शिव के रूप दिखना कोई साधारण बात नहीं है।’

तीर्थयात्रियों के लिए नया आकर्षण इन चट्टानों को देखने के लिए अब केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लोग इन्हें आस्था का प्रतीक, चमत्कार का संकेत, प्रकृति की अद्भुत कला और शिव की कृपा मानकर प्रति दिन बड़ी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं।

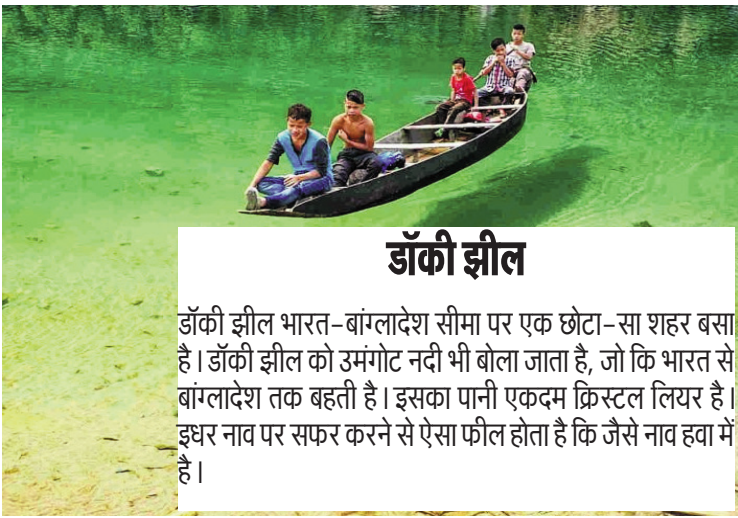
रहस्य और श्रद्धा बढ़ाती अनोखी कहानी चाहे ये आकृतियां संयोग हों या प्रकृति के अद्भुत खेल— केदारनाथ की ये चट्टानें अब एक नई आध्यात्मिक कहानी बन चुकी हैं। 2013 की त्रासदी के दौरान मंदिर को बचाने वाली ये चट्टानें आज श्रद्धालुओं की आस्था का नया केंद्र बनकर उभर रही हैं। यह घटना बताती है कि प्रकृति और आस्था जब मिलती हैं, तो इतिहास खुद-ब-खुद नई कहानी रच देता है।



बादलों का घर मेघालय : इन 5 जगहों की सैर आपको जीवन भर याद रहेगी, बनाएं ट्रिप का प्लान !

नॉर्थ-ईस्ट राज्य प्राकृति और सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। अगर आप मेघालय जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। यहां की सुंदरता दुनियाभर में फेमस है। मेघालय में पानी भी शीशे की तरह चमकता है और घने जंगल की सुंदरता देखकर आप कहीं न कहीं खो जाएंगे। जो एक बार मेघालय घूमने जाएगा वो वही का होकर रह गया है। मेघालय में आपको पहाड़, झरने, नदियां, झील, हरे जंगल सबकुछ देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं आप किन जगहों पर जरूर घूमने जाएं।

शिलॉन्ग



डॉकी झील

डॉकी झील भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक छोटा-सा शहर बसा है। डॉकी झील को उमंगोट नदी भी बोला जाता है, जो कि भारत से बांग्लादेश तक बहती है। इसका पानी एकदम क्रिस्टल लियर है। इधर नाव पर सफर करने से ऐसा फील होता है कि जैसे नाव हवा में है।

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग घूमने जरूर जाएं। यह शहर बेहद ही खूबसूरत और हरियाली से घिरा हुआ है। मेघालय पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है शिलॉन्ग। इसे मिनी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलॉन्ग में आप व्यू पॉइंट, लैक्कोर पीक, स्प्रेड ईगल फॉल्स, लेडी हार्टरी पार्क और एलिफेंट फॉल्स को जरूर देखें।

दावकी

अगर आप मेघालय जा रहे हैं, तो पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी छोटा सा टाउन है, यहां पर घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। इधर आपको सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। दावकी में

खूबसूरती और रोमांच का अनोखा संगम, हिमाचल का ‘कौमिक’ गांव, जहां चांदनी रातें बिखेरती हैं जादू

उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत खाबों की दुनिया में चला जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमाचल के हृदय में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसको उत्तराखंड की तरह ही ‘देव भूमि’ के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो ‘बर्फीले पहाड़ों के प्रांत’ के नाम से फेमस है। उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत खाबों की दुनिया में चला जाएगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कौमिक की खासियत और इसके आसपास

कुछ अद्भुत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। **कौमिक गांव**

कौमिक गांव को कई लोग कौमिक के नाम से भी जानते हैं। यह गांव खूबसूरत और मनमोहक गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है।

कौमिक गांव हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 444 किमी दूर है। इसके साथ ही कौमिक गांव मनाली से 202, कुल्लू से 224 और रिकांग पिओ से करीब 228 किमी दूर है।

कौमिक गांव की खासियत

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की स्पीति में स्थित कौमिक गांव काफी ज्यादा खूबसूरत है। कौमिक गांव को भारत के अलावा दुनिया के सबसे गांव होने की ख्याति भी प्राप्ति होती है।

कौमिक गांव समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद कौमिक गांव ढके-ढके ऊंचे पहाड़, क्रिस्टल से अधिक साफ झील-झरनों का पानी और नीले आसमान के लिए जाना जाता है। कौमिक गांव की चांदनी रात पर्यटकों को



सबसे अधिक आकर्षित करती है। यहां का शांत और शुद्ध वातावरण भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसलिए इस गांव को हिमाचल प्रदेश का हसीन जन्म माना जाता है।

लुंडुप त्सो गोम्पा बौद्ध मठ

कौमिक गांव अपनी खूबसूरती के अलावा लुंडुप त्सो गोम्पा बौद्ध मठ के लिए भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस मठ के बारे में बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 500 साल से भी अधिक पुराना है।

पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होने के कारण लुंडुप त्सो गोम्पा बौद्ध मठ को एक्सप्लोर करना बहुत लोगों का सपना होता

है। मठ की ऊंचाई से कौमिक गांव के आसपास के लुभावने और हसीन दृश्यों को आंखों में कैद कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर यादगार फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग

यह गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि गोम्पा बौद्ध मठ और एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यह गांव विश्व भर में सबसे ऊंचे ट्रेकिंग और हाईकिंग के लिए फेमस है।

सर्दियों के मौसम के अलावा आप यहां पर गर्मियों में भी आ सकते हैं। यहां पर हजारों लोग ट्रेकिंग, बाइक राइड और कैपिंग

ऐसे पहुंचें कौमिक गांव

बता दें कि इस गांव पहुंचना बेहद आसान है। इसके लिए आप दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बस लेकर स्पीति वैली पहुंच सकते हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से स्पीति वैली के लिए बस चलती है। स्पीति वैली पहुंचने के बाद आप बाइक रेंट पर लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला से भी बस लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं।

के लिए भी आते हैं। आप यहां पर रॉक क्लाइंब का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

ये कैसा झरना जो बहता है उल्टा ! नीचे गिरने की बजाए ऊपर चढ़ता है पानी, देखकर हिल जाएगा दिमाग

वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसी तेज हवा की दिशा और गति के कारण यह झरना उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है, जो इसे बेहद रहस्यमयी और अनोखा बनाता है।

इसे देखने पर क्या महसूस होता है ?

जो भी इस झरने को पहली बार देखता है, वह दंग रह जाता है। दूर से ऐसा लगता है मानो पानी ऊंची पहाड़ी की तरफ ऊपर बढ़ रहा हो। यह अद्भुत नजारा लोगों को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर देता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा उल्टा करिश्मा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता।

कैसे पहुंचें नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल ?

अगर आप नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां पहुंचना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको कल्याण बस स्टैंड जाना होगा, जहां से जून 7 नगर और नानेघाट के लिए नियमित बसें मिल जाती हैं। चाहें तो आप सड़क मार्ग से भी अपनी कार या टेक्सी से आराम से नानेघाट

पहुंच सकते हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता सुंदर घाटों और हरियाली से भरा है, जो यात्रा को और भी खास बनाता है।

ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग

नानेघाट ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह ट्रेल घाटघर के घने जंगल क्षेत्र का हिस्सा है और रोमांच से भरपूर प्राकृतिक रास्तों से होकर गुजरता है। कल्याण-अहमदनगर हाईवे से शुरू होने वाला यह ट्रेकिंग रूट साहसिक यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां का शांत वातावरण, पहाड़ी दृश्य और ठंडी हवाएं पूरे सफर को यादगार बना देती हैं।

घूमने का सबसे अच्छा समय

नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम माना जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच यहां की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस दौरान हवाएं बेहद तेज चलती हैं, जिसकी वजह से झरना सबसे मनमोहक तरीके से उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है। यहीं

समय इस अनोखे प्राकृतिक चमत्कार को नजदीक से देखने के लिए परफेक्ट माना जाता है।



भारत में प्रकृति के कई ऐसे चमत्कार हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जायेंगे। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का नानेघाट वाटरफॉल, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता है। आमतौर पर झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन यह झरना नीचे से ऊपर बहता दिखाई देता है। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

कहा स्थित है यह अनोखा झरना ? यह अनोखा झरना नानेघाट वाटरफॉल के नाम से मशहूर है और कोंकण समुद्र तट तथा जुन्नार नगर के बीच स्थित है। मुंबई से

इसकी दूरी करीब 120 किमी और पुणे से लगभग 150 किमी है। नाना घाट और ‘रिवर्स वाटरफॉल’ के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपने अनोखे प्राकृतिक दृश्य के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है।

क्यों बहता है यह झरना उल्टी दिशा में ?

गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक हर चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन नानेघाट का यह झरना तेज हवाओं के कारण ठीक उल्टा व्यवहार करता है। यहां हवा इतनी तेज चलती है कि नीचे गिरता पानी हवा का दबाव पकड़कर ऊपर उड़ने लगता है।

संक्षिप्त समाचार

श्रीलंका का पूर्व टेस्ट क्रिकेटर गिरफ्तार

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और वलंड कप जीतने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा के बड़े भाई दमिका को देश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने गिरफ्तार किया और बाद में सोमवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। भ्रष्टाचार जांच आयोग ने बताया कि 63 साल के दमिका को 2017 में सरकारी कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा कच्चे तेल की खरीद में गलत टेंडर प्रक्रिया के लिए गिरफ्तार किया गया था, जब वह इसके चेयरमैन थे। भ्रष्टाचार जांच आयोग ने कहा कि दमिका के अनुचित प्रभाव के कारण सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 800 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का नुकसान हुआ।

नेपाल में भारतीय राजदूत के स्वास्थ्य में सुधार

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव को स्टेट डाला गया है। उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। राजदूत को शुक्रवार को चंपादेवी पहाड़ी पर हाइकिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर से ग्रांडी अस्पताल लाया गया। जांच में हृदय की बाई धमनी में ब्लॉकज मिलने पर स्टेट डाला गया।

बलोच नेता की अपील-पाकिस्तानी कब्जे को बेनकाब करती फिल्में बनाएं

वाशिंगटन, एजेंसी। बलोच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने भारतीय फिल्म उद्योग से ऐसी फिल्में बनाने की अपील की है, जो बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के जबरन और अलोकतांत्रिक कब्जे को दिखाएं। उन्होंने सीशल मीडिया पर कहा कि, बलूचिस्तान ने मार्च 1948 में पाकिस्तान के कब्जा करने से पहले ही स्वतंत्रता हासिल की थी। चंद ने आरोप लगाया कि इस कब्जे के बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के अरबी डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से लूटा है।

मोरक्को के साफी में आई बाढ़ से 37 मौतें

साफी, एजेंसी। मोरक्को के साफी शहर में भारी बारिश से आई बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो गई है। गुह मंत्रालय ने कहा, रात भर अचानक हुई भारी बारिश से आई बाढ़ से कई घर-व्यवसाय जलमग्न हो गए और 10 वाहन बह गए। स्कूलों को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण अन्य हिस्सों में भी बाढ़ आई है, जिनमें तटीय शहर टेदुआन और पहाड़ी शहर टिंगहिर शामिल हैं।

हांगकांग : लोकतंत्र समर्थक जिम्मी लार्ड दोषी करार

विक्टोरिया, एजेंसी। स्वायत्तशासी क्षेत्र हांगकांग की प्रसिद्ध मीडिया हस्ती रहे और चीन के मुखर आलोचक जिम्मी लार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक ऐतिहासिक मामले में सोमवार को शहर की अदालत ने दोषी ठहराया। सरकार द्वारा नियुक्त तीन जजों ने 78 वर्षीय लार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा में डालने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करने और राजद्रोहपूर्ण लेख प्रकाशित करने की साजिश रचने का दोषी पाया। हालांकि लार्ड ने खुद को निर्दोष बताया है। हांगकांग के कानून के तहत लार्ड को उम्रकैद की सजा हो सकती है।

हत्या मामला : मुकदमे का सामना कराने के लिए पैरु से अमेरिका लाया गया व्यक्ति

लॉस एंजेलिस, एजेंसी। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगल में अपनी पत्नी की हत्या करने और उसका शव फेंकने के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए एक व्यक्ति को पैरु से अमेरिका लाया गया। लॉस एंजेलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लॉस एंजेलिस काउंटी शेरिफ विभाग ने कहा, जोसिमार कैबरा (36 वर्षीय) शुक्रवार रात लॉस एंजेलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसे अगस्त के अंत से पैरु में हिरासत में रखा गया था। जिला अदालती कार्यालय ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दायर किया है। रविवार तक यह पता नहीं था कि उसके पास वकील है या नहीं।

नेपाल में भारतीय राजदूत के स्वास्थ्य में सुधार

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव को स्टेट डाला गया है। उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। राजदूत को शुक्रवार को चंपादेवी पहाड़ी पर हाइकिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर से ग्रांडी अस्पताल लाया गया।

जयशंकर ने यूएई के शीर्ष नेतृत्व के साथ की बैठक, आर्थिक और रक्षा सहयोग पर हुई सार्थक चर्चा

अबू धाबी, एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर भारत-यूएई संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की है। इन बैठकों में आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और रणनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब भारत और यूएई के रिश्ते तेजी से बहुआयामी रूप ले रहे हैं और क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की भूमिका अहम मानी जा रही है।

विदेश मंत्री जयशंकर तीन दिन तक चले सिर बनी यास फोरम 2025 में हिस्सा लेने के बाद सोमवार को अबू धाबी पहुंचे। यहां उन्होंने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ 16वीं संयुक्त आयोग बैठक और पांचवें रणनीतिक संवाद की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की

गई और भविष्य की प्राथमिकताओं पर सहमति बनी।
आर्थिक और रक्षा सहयोग पर जोर : जयशंकर ने यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक में आर्थिक सहयोग को गहरा करने और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इसे बेहद उपयोगी बातचीत बताया और कहा कि दोनों देश आपसी विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम माना गया।

निवेश और भू-आर्थिक हालात पर बातचीत : विदेश मंत्री जयशंकर ने मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खालदून खलीफा अल मुबारक से भी मुलाकात की। मुबादला अबू धाबी सरकार की प्रमुख संप्रभु निवेश कंपनी है। इस बातचीत में वैश्विक भू-आर्थिक

स्थिति पर विचार साझा किए गए और भारत-यूएई आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया। जयशंकर ने भारत में उभरते निवेश अवसरों की जानकारी भी दी।

रणनीतिक संवाद को मिली नई दिशा : भारत और यूएई के बीच हुए रणनीतिक संवाद में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने माना कि मौजूदा वैश्विक हालात में एक-दूसरे के साथ तालमेल और मजबूत करना

जरूरी है। यह संवाद भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर ठोस बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
अगला पड़ाव इस्त्राइल यात्रा : यूएई दौरे के बाद विदेश मंत्री जयशंकर मंगलवार को इस्त्राइल की यात्रा पर जाएंगे। वहां वे अपने समकक्ष गिडिओन सआर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके अलावा जयशंकर की इस्त्राइल के राष्ट्रपति आइजक हज्जों और प्रधानमंत्री बेजर्मिन नेतन्याहू से भी मुलाकात तय है। इस्त्राइल दौरे में क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जयशंकर का यह दौरा भारत की सक्रिय और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है। यूएई जैसे अहम साझेदार के साथ रिश्तों को और मजबूत करना भारत की प्राथमिकता है। आर्थिक निवेश से लेकर रक्षा सहयोग और रणनीतिक संवाद तक, यह यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया हमले पर बड़ा खुलासा- इस्लामिक स्टेट से ली प्रेरणा, फिलीपींस गए थे बाप-बेटा

सिडनी, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर रविवार शाम को हुए सामूहिक गोलीबारी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। यह हमला यहूदी समुदाय के हानुका उत्सव 'चानुका बाय द सी' के दौरान हुआ, जिसमें करीब एक हजार लोग शामिल थे। पुलिस ने इसे आतंकी घटना घोषित कर दिया है और प्रारंभिक जांच से संकेत मिल रहे हैं कि हमलावर इस्लामिक स्टेट (आईएस) की विचारधारा से प्रेरित थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को कहा कि हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित लगता है। उन्होंने इसे नफरत की विचारधारा करार दिया, जो पिछले एक दशक से कुछ लोगों को उग्रवादी बनाने का काम कर रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमलावरों की कार में दो घरेलू स्तर पर बने इस्लामिक स्टेट के झंडे और इश्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) मिले हैं।

हमलावरों की पहचान : हमलावर पिता-पुत्र थे। 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने इस हमले को अंजाम दिया। साजिद अकरम की पुलिस की गोलीबारी में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नवीद गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में पुलिस हिरासत में है। साजिद के पास छह हथियारों का वैध लाइसेंस था, जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया लगता है। पुलिस कमिश्नर माल लैन्यन ने



बताया कि दोनों हमलावर पिछले महीने फिलीपींस की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा के उद्देश्य की जांच चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में संकेत है कि वे वहां मिलिट्री ट्रेनिंग लेने गए थे। नवीद अकरम की 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी एएसआईओ ने जांच की थी, क्योंकि उसके आईएस से जुड़े एक सेल से संबंध थे, लेकिन तब उसे तत्काल खतरा नहीं माना गया।

हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) की विचारधारा से प्रेरित था: एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) की विचारधारा से प्रेरित था। समाचार एजेंसी एएफपी और बीबीसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अल्बनीज ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। यह बात उन्होंने

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) के सिडनी चैनल को दिए गए एक रेडियो इंटरव्यू में कही, जिसके अंश उनके कार्यालय ने समाचार एजेंसियों के साथ साझा किए। उन्होंने इस हमले को 'सुनियोजित, योजनाबद्ध और बेहद बर्बर' बताया। अल्बनीज ने कहा कि अब तक की जांच से संकेत मिलता है कि दो हमलावरों (जो पिता और बेटे की जोड़ी थे) ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्बनीज ने कहा कि यह वह विचारधारा है जो एक दशक से ज्यादा समय से मौजूद है, जिसने नफरत की सोच को जन्म दिया और इसने बड़े पैमाने पर हत्या करने की मानसिकता पैदा की। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावर नवीद अकरम पहले भी दूसरों के साथ उसके संबंधों की वजह से अधिकारियों की नजर में आया था। नवीद का पिता साजिद अकरम पुलिस

की गोलीबारी में मारा गया था।

रिपोर्ट में प्रधानमंत्री अल्बनीज के हवाले से कहा गया, जिन दो लोगों से वह (नवीद) जुड़ा हुआ था, उन पर आरोप लगे और वे जेल भी गए। लेकिन उस समय उसे ऐसा व्यक्ति नहीं समझा गया था कि जिस पर विशेष नजर रखने की जरूरत हो। अल्बनीज की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि साजिद और नवीद अकरम इस्लामिक स्टेट से प्रभावित थे।

कानून प्रवर्तन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एबीसी को बताया था कि इसकी संभावना है, क्योंकि हमलावरों की कार से कथित तौर पर आईएस एक का झंडा बरामद हुआ था। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लान्योन के अनुसार, इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई, इसके अलावा एक हमलावर भी मारा गया। मृतकों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल थी। बॉन्डी बीच गोलीबारी के पीछे शामिल दोनों हमलावरों की पहचान सोमवार सुबह (स्थानीय समय) की गई। पुलिस आयुक्त लान्योन ने बताया कि 50 वर्षीय और 24 वर्षीय दो पुरुष ही इस हमले में शामिल एकमात्र शूटर थे। नवीद अकरम को घटनास्थल से गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने यह भी बताया कि उसके पिता साजिद अकरम को हमले के दौरान पुलिस ने गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मेक्सिको में प्लेन फैक्ट्री से टकराई, 7 की मौत, 3 लापता; इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में हादसा



मेक्सिको, एजेंसी। मेक्सिको में सोमवार को एक छोटा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इसमें सात लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लापता हैं। यह प्राइवेट जेट एकापुल्को से टोलुका एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में सैन मेटियो एंटों इलाके में क्रैश हो गया। विमान ने एक फुटबॉल फील्ड पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पास की एक फैक्ट्री की मेटल छत से टकरा गया, जिससे आग लग गई।

आग की वजह से इलाके के करीब 130 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। दुर्घटना की जांच चल रही है, और शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन फेलियर की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि प्राइवेट जेट में 8 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर थे। फिलहाल 7 लोगों के शव मिले हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है।

छत से टकराया विमान : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,

विमान एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह पास में स्थित एक व्यावसायिक इमारत की लोहे की छत से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई, जिसने आसपास के क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर दमकल और बचाव दल पहुंचे और आग पर काबू पाया। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

इलाके से 130 लोगों को निकास किया बाहर : सैन मातेओ अतेन्को की मेयर आना मुनिज ने बताया कि आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के करीब 130 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने एहतियातन पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह साफ हो पाएगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी पर ठोक दिया मानहानि का मुकदमा, मांगा 10 अरब डॉलर का हर्जाना



मानहानिकारक, भ्रामक, अपमानजनक, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण चित्रण' करने का आरोप लगाया गया है और इसे 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 'हस्तक्षेप करने तथा उसे प्रभावित करने की निर्लज्ज कोशिश' बताया गया है। इसमें बीबीसी पर 'राष्ट्रपति ट्रंप के छह जनवरी, 2021 के भाषण के दो पृष्ठ तरह से अलग-अलग अंशों को एक साथ जोड़ने' का आरोप लगाया गया ताकि 'ट्रंप द्वारा कही

गई बातों के अर्थ को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।' बता दें कि बीबीसी की फॉडिंग उसके दर्शकों से होती है। डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम का कहना है कि बीबीसी लेफ्ट अजेंडा चलाता है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। बीबीसी की तरफ इस मुकदमे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित करने को लेकर बीबीसी पहले से ही

संकट का सामना कर रहा है। कई सीनियर अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। इससे बीबीसी की छवि भी खराब हुई है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका में नहीं प्रसारित किया गया था। अब अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी वाले कानून से अपने मुद्दे को अलग करने के लिए ट्रंप को साबित करना होगा कि बीबीसी ने जो कुछ भी एडिट किया वह अपमानजनक था और दर्शकों में भ्रम फैलाने के लिए ही ऐसा किया गया था। बीबीसी कोर्ट में दावा कर सकता है कि उसने जो कुछ दिखाया वह सच था और जो कुछ भी एडिट किया गया है उससे जनता में कोई गलत संदेश नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ भी केस किया था। हालांकि दोनों ने किसी भी गलती से इनकार किया है।

‘रूस-यूक्रेन शांति समझौता के बहुत करीब’, बर्लिन में बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा



वाशिंगटन, एजेंसी। तीन साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस और यूक्रेन संघर्ष इतने प्रयासों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस संघर्ष के जल्द खत्म होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन शांति समझौते को लेकर पहले से कहीं ज्यादा करबी आ चुके हैं। यह दावा उन्होंने अमेरिकी समयानुसार सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बर्लिन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत के बाद हालात बेहतर होते दिख रहे हैं।

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब बर्लिन में अमेरिका, यूरोपीय देशों, नाटो के नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कई घंटे तक बातचीत हुई। इन बैठकों में युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय देश

यूक्रेन को पश्चिमी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किस इलाके पर किसका नियंत्रण रहेगा, यह मुद्दा अब भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है।
अमेरिका को मिल रहा यूरोप के कई देशों का साथ-ट्रंप : ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका को यूरोप के कई देशों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे जरूर पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि अब यह संघर्ष खत्म होने के पहले से ज्यादा करीब है। ट्रंप ने देशों के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

इतना ही नहीं ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत होने की बात का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बातचीत हुई हैं और सब मानते हैं कि हम समाधान के बहुत नजदीक हैं। हम बहुत सारी जिंदगियां बचाना चाहते हैं।

तिरुपति में मुंडन सेवा के लिए कारोबारी ने 1 करोड़ 20 लाख के हाफ ब्लेड दान किए

हैदराबाद (एजेंसी)। दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को एक खास दान प्राप्त हुआ। हैदराबाद के एक बिजनेसमैन श्री श्रीधर ने मंदिर की मुंडन रस्मों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के हाफ ब्लेड दान किए हैं। बिजनेसमैन श्रीधर ने कल्याणकट्टी (मुंडन केंद्रों) की सालाना जरूरत को पूरा करने के लिए काफी संख्या में हाफ ब्लेड दान कर दिए हैं। जिनकी कीमत 1.2 करोड़ रुपए के करीब है। मौड्या रिपोर्ट में बताया, बिजनेसमैन बी श्रीधर ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 1.2 करोड़ रुपए के हाफ ब्लेड दान किए हैं। टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू ने कहा कि मंदिर संस्था हर साल भक्तों के बाल मुंडवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लेड पर करीब 1.1 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो भगवान को अपने बाल चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कल्याणकट्टी में रोजाना करीब 40 हजार हाफ ब्लेड इस्तेमाल होते हैं और श्रीधर के दान से मंदिर की पूरे साल की जरूरत पूरी होगी। बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है, जो विश्व का सबसे धनी हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बाल दान कराते हैं, जिसे मुंडन सेवा कहा जाता है।

भाजपा सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवक के रुप में काम कर रही - सीएम शर्मा

बीकानेर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को गणेश मानकर सेवक के रूप में काम कर रही है। सीएम शर्मा बीकानेर के लूणकरणसर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट दिया और हर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ के माध्यम से विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचा रही है।' उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने दो साल में राज्य में सुशासन, जनकल्याण और बहुमुखी विकास के लिए 48 इस्तरह के अमृतप्लव कर्म उठाए हैं, जो ऐतिहासिक होने के साथ ही समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की एक सशक्त बुनियाद भी हैं।' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए कईकदम उठाए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने 612 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 107 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बीकानेर की जिला विकास पुस्तिका, ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी तथा 'शहरी सेवा शिविर -2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया।

श्रीजगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर वायरल अंदर की तस्वीरें

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी जिले स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था फिर सवाल उठ गए हैं। सोशल मीडिया पर फिर श्रीजगन्नाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि एक इंटरनेट मीडिया आईडी से रत्नसिंहासन पर विराजमान महाप्रभु श्रीजगन्नाथ की तस्वीरें साझा की गई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फोटों को अत्यंत नजदीक से लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि कड़ी जांच व्यवस्था के बावजूद मोबाइल फोन मंदिर परिसर के भीतर कैसे पहुंचा, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नागरत तस्वीरों के साथ संबंधित व्यक्ति ने पुरी मंदिर के बाहर अपनी तस्वीरें भी अपलोड की हैं। कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें वायरल होने से मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह मामला न केवल आस्था, बल्कि मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर भी इशारा करता है। जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

चंडीगढ़(एजेंसी)। हरियाणा में गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र एगामेदार होने के आसार हैं। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। पूर्व सीएम एवं विधेयक के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हरियाणा में 'वोटों की चोरी' करके सरकार बनाई है। कांग्रेस नेता हुड्डा ने दावा किया कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले अंधे गोलभोजन देने और एक ही व्यक्ति के लिए कई वोट बनाने जैसे हथकंडों का सहारा लिया। इसलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके गतत कामों का सदन में पर्दाफास किया जाएगा।

गौरव गोगोई ने अटकलों को दिया विराम कहा- एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस नहीं करेगी गठबंधन

गोवाहाटी (एजेंसी)। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने उन तमाम अटकलों को विराम दे दिया, जिसके तहत कहा जा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन करेगी। इस पर गोगोई ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस तरह का कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने एआईयूडीएफ को सांप्रदायिक संगठन बताया और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में विपक्षी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। पहले ही, आठ विपक्षी दलों ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने के लिए अगले साल के विधानसभा चुनावों में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। गोगोई ने यहां पत्रकारों से कहा, '‘किसी भी परिस्थिति में एआईयूडीएफ के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। गोगोई ने दावा किया, भाजपा पहले ही देख चुकी है कि मौजूदा नेतृत्व में उसके भविष्य की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास है कि भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता पार्टी से निराश हो रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में देश से माफी मांगे पीएम नरेंद्र मोदी: राजेश राम

- ईडी की भूमिका संदिग्ध, हमारे नेताओं को भाजपा के इशारे पर बदनाम करने की रच रहा है साजिश- राजेश राम

नई दिल्ली(एजेंसी)। पटना, (ईएमएस)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को राजनीतिक द्वेष के तहत फँसाने हेतु केंद्र सरकार के इशारे पर नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को राउज एवेन्यू कोर्ट से संज्ञान लेने से इंकार करने को जीत बताते हुए भाजपा के नीतियों के विरोध में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में विरोध मार्च पटना के आयकर गोलंबर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक आयोजित हुआ। इस विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। अदालत ने दोनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दोनों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। जबकि ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाहक परेशान करने के लिए



आरोपी बनाया। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। इस सत्ताधारी भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। साथ ही बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट

(पीएमएलए) के मामलों में दोष सिद्ध की दर 10 प्रतिशत से भी कम है। इसलिए यह केस केवल गांधी परिवार को बदनाम करने और देश में कांग्रेस की छवि को भाजपा के इशारे पर बिगाड़ने के लिए बार बार उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में संज्ञान नहीं लेने पर हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और ईडी की भूमिका को संदिग्ध मानते हैं। इसीलिए हम आज

ममता का बचाव कर अभिषेक ने कहा... झुकता वहीं है जिसमें जान है, वरना अकड़ मुर्दों की पहचान

कोलकाता (एजेंसी)। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कोलकाता दौर के दौरान हुई अव्यवस्था और उस पर मची राजनीतिक हलचल ने राज्य का पारा चढ़ा रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला और अन्य राज्यों की घटनाओं का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव किया है।



सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में हुई दुर्घटनाओं (जैसे कुंभ और दिल्ली रेलवे स्टेशन का भगदड़) का जिक्र कर कहा कि वहां किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना के एक घंटे के भीतर माफी मांग ली। उन्होंने इसके लिए एक शेर का उपयोग किया कि झुकता वहीं है जिसमें जान है, वरना अकड़ मुर्दों की पहचान है। उनके अनुसार, जवाबदेही तय करना ही टीएमसी की जीत का कारण है। दरअसल मेसी का गेटा टूर 2025 कोलकाता के शॉर्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था का शिकार

हो गया था। फुटबाल प्रशंसकों का आरोप है कि मैदान पर वीआईपी और राजनेताओं की अत्यधिक भीड़ के कारण आम दर्शक मेसी को देख नहीं पाए। टिकट खरीदने के बावजूद मेसी की झलक न मिलने पर प्रशंसकों ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की। आयोजकों पर सुरुक्षा और समन्वय की कमी के गंभीर आरोप लगे। विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। ममता सरकार में खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। घटना की जांच के लिए चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाई गई है। छीजीपी राजीव कुमार को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

बीजेपी के केन्द्रीय मंत्री का दावा... राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड़ा के बीच झगड़ा

-बीजेपी का आरोप, कांग्रेस की आंतरिक कलह अब बाहर आ गई

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिड़ू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड़ा के बीच विवाद को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष परिवार से झगड़ा कर विदेश चले गए हैं। फिलहाल, बीजेपी नेता के इन दावों पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से निकाले गए नेता मोहम्मद मुकीम के पत्र के हवाले से इस्तराफ का दावा किया था।

केन्द्रीय मंत्री बिड़ू से कांग्रेस के प्रदर्शन की तैयारी पर सवाल पूछा गया। इसपर उन्होंने कहा, उनके पास लोग हैं प्रदर्शन करने के लिए? उन्हें महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो उनका गांधी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, उन्हें उस गांधी से दिकत है कि वहां कहां जा रहा है। उन्होंने कहा, लोग उस गांधी को भूल चुके हैं, जो उनके नाम से



जुड़ा हुआ है। उस गांधी को नकार चुके हैं। और बापू गांधी थे हैं और हमेशा रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी हैं कहां? अभी मैं उनकी तस्वीरें जर्मनी में देख रहा था। उन्होंने कहा, दोनों गांधी में लड़ाई चल रही है, बड़ी भारी लड़ाई चल रही है। जो मुझे पता लगा है... सदन में जो दो तीन बार जो भाषण हुआ है, उस भी लोगों ने प्रियंका गांधी वाड़ा का जो भाषण है, उसकी तुलना की है। और राहुल गांधी इस चीज से नाराज होकर परिवार और पार्टी से लड़कर यहां से चले गए हैं।

उन्होंने कहा, उनकी पार्टी और फैमिली में जो प्रॉब्लम है। इसलिए राहुल गांधी छोड़कर चले गए हैं। बात दें कि इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा था, टीम प्रियंका बनाम टीम राहुल खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस की आंतरिक कलह अब बाहर आ गई है। उन्होंने लिखा, ओडिशा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को लिखा कि खरों हटाओ, प्रियंका लाओ। साथ ही प्रदेश और

देहरादून (एजेंसी)। जबन धर्मांतरण के मामलों में सजा का दायरा बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल सकी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मीत सिंह (सेन) ने इस विधेयक को पुर्नविचार के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विधेयक के मसौदे में कुछ तकनीकी खामियों के कारण यह निर्णय लिया गया। विधायी विभाग को यह विधेयक मंगलवार को प्राप्त हुआ।



सरकार के सामने अब इस विधेयक को लागू करने के लिए सीमित विकल्प रह गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, या तो सरकार अयोध्या के जरिए इसे प्रभावित बनाए, अथवा अगले विधानसभा सत्र में इसे संशोधनों के साथ दोबारा पारित कराए। धामी सरकार के लिए यह विधेयक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जबन और

स्वीकृति के लिए भेजा गया।

-राजा और प्रावधानों में बड़े बदलाव...

नए विधेयक में छल, दबाव या प्रलोभन से धर्मांतरण कराने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकेगा, जबकि पहले यह दायरा केवल खून के रिशतों तक सीमित था। सामान्य धर्म परिवर्तन के मामलों में जेल की सजा को बढ़ाकर तीन से दस वर्ष कर दिया गया है, जो पहले दो से सात वर्ष थी। इसके अलावा जिलाधिकारी को गैंगस्टर एक्ट की रजर्ज पर संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। विवाह का झंझा देकर, हमला, भ्रष्टाचर, नाबालिगों की तस्करी, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के जरिए धर्मांतरण कराने पर न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में दोनोंपक्ष पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

बॉन्डी बीच पर हमला करने वाला साजिद हैदराबाद का रहने वाला

-तेलंगाना पुलिस ने किया खुलासा, रोजगार की तलाश में चला गया था आस्ट्रेलिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुक्का कार्यक्रम में हुए आतंकी हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस तक कई एजेंसियां इस आतंकी साजिश के तार खंगालने में जुटी हैं। शुरूआती रिपोर्ट्स में हमलावरों को पाकिस्तानी मूल का बताया था, लेकिन भारत के तेलंगाना पुलिस के मुताबिक

साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था और उसने वहीं से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी।

वर्ष 1998 में रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और बीते करीब 27 सालों से उसका भारत से कोई संबंध नहीं रहा। पुलिस के मुताबिक साजिद ने इस दौरान केवल छह बार भारत आया यहां तक कि पिता के निधन के समय भी वह भारत नहीं आया। तेलंगाना पुलिस ने साफ किया है कि इस हमले के पीछे भारत या तेलंगाना से जुड़ा कोई स्थानीय लिंक नहीं है और कट्टरपंथी विचारधारा के सूत्र विदेश में ही विकसित हुए हैं।

तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद

अकरम के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट था, लेकिन भारत से उसका रिश्ता सीमित था। पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वह केवल छह बार ही भारत आया और वहां भी मुख्य रूप से संपर्कित से जुड़े कामों या बुजुर्ग माता-पिता से मिलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में बसने के बाद साजिद ने यूरोपीय मूल की महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की। उनके दो बच्चे हुए, जिसमें एक बेटी नावेद अकरम और एक बेटा है। दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं।

बात दें 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान हुए आतंकी हमले में साजिद और उसके बेटे

नावेद अकरम ने गोलीबारी की। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई और 42 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस मुठभेड़ में साजिद मारा गया, जबकि नावेद गंभीर रूप से घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में है। जांच में सामने आया है कि हमले से कुछ हफ्ते पहले साजिद और नावेद फिलीपींस गए थे। वे 1 नवंबर 2025 को सिडनी से फिलीपींस पहुंचे और 28 नवंबर को वापस लौटे। उन्होंने मिंडानाओ के दावाओ क्षेत्र की यात्रा की थी, जो पहले आईएस से जुड़े आतंकी नेटवर्क के लिए जाना जाता रहा है।

बॉन्डी बीच हमला ऑस्ट्रेलिया में पिछले करीब 30 सालों का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला माना जा रहा है।

वेरिफिकेशन के बाद पांच राज्यों में वोटर लिस्ट जारी, एक करोड़ से ज्यादा नाम कटे



नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कराए गए एसआईआर या सामान्य शब्दों में कहे वोटर वेरिफिकेशन के बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 7.6फीसदी की कमी दर्ज की गई है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय जहां इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे, वहीं ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं। बंगाल में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए वृद्धित किए गए हैं। वहीं राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसके साथ ही घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है। अब आगे दावा, आपति और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। इसके साथ ही गोवा और लक्षद्वीप में भी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित की जाएगी।

पाकिस्तान के कुख्यात डॉन भट्टी ने दी नीतीश को धमकी... हिजाब मामले में माफी मांगे ले

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचने के विवाद में अब पाकिस्तानी डॉन भी कूद गया है। पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी कर धमकी दी है कि सीएम नीतीश माफी मांग लें वरना फिर ये मत कहना है कि चेतावनी नहीं दी।



दरअसल पटना में नवनिर्गुण एक आयुष चिकित्सक तब असहज हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश ने निर्गुण पत्र प्रदान करने के दौरान उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया। पटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय 'संवाद' में एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां एक हजार से अधिक आयुष

चिकित्सकों को निर्गुण पत्र वितरित किए जा रहे थे।

निर्गुण पत्र देने के दौरान जब नुसरत परवीन की बारी आई, जो चेहरे पर हिजाब डाले हुई थीं, तब 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने

नाराजगी जताकर कहा, "यह क्या है?" इसके बाद मुख्यमंत्री उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया। घबराई हुई नवनिर्गुण चिकित्सक को इसके बाद वहां मौजूद एक अधिकारी ने तुरंत एक ओर कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के

बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने के प्रयास में उनकी आस्तीन खींचते हुए नजर आए। इस पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने अपना वीडियो जारी कर कहा है कि सभी लोगों ने देखा होगा कि बिहार में क्या हुआ। एक बड़े पत्र पर बैठा व्यक्ति एक मुस्लिम महिला के साथ व्यवहार करता है। फिर बाद में मुझपर आरोप लगाए जाते हैं कि भट्टी ने यह कर दिया, वह कर दिया। उस व्यक्ति के पास अभी भी समय है कि वह उस बच्ची और उस महिला से माफी मांगे। अगर आज माफी नहीं मांगी गई, तब जिम्मेदार संस्थानों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में यह मत कहना है कि चेतावनी नहीं दी गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहजाद भट्टी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है।

उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरा, उड़ानों में देरी की संभावना- मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। (एजेंसी)। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्से इस समय घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दृश्यता कम होने के कारण सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार रात को यात्रियों के लिए टूटल एडवाइजरी जारी की। इंडिगो ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान संचालन में बदलाव किया जा सकता है। एयरलाइन की टीमें एयरपोर्ट पर पूरी तरह तैयार हैं और वे पलाइंट शेड्यूल को अपडेट करने तथा यात्रियों की मदद के लिए काम कर रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घने कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचें, पलाइंट की सही टाइमिंग और अपडेट के लिए इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप चेक करें एवं किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें।

धर्मांतरण कानून पर रोक ! राज्यपाल ने लौटा दिया उम्रकैद की सजा वाला बिल

देहरादून (एजेंसी)। जबन धर्मांतरण के मामलों में सजा का दायरा बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल सकी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मीत सिंह (सेन) ने इस विधेयक को पुर्नविचार के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विधेयक के मसौदे में कुछ तकनीकी खामियों के कारण यह निर्णय लिया गया। विधायी विभाग को यह विधेयक मंगलवार को प्राप्त हुआ।



सरकार के सामने अब इस विधेयक को लागू करने के लिए सीमित विकल्प रह गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, या तो सरकार अयोध्या के जरिए इसे प्रभावित बनाए, अथवा अगले विधानसभा सत्र में इसे संशोधनों के साथ दोबारा पारित कराए। धामी सरकार के लिए यह विधेयक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जबन और

स्वीकृति के लिए भेजा गया।

-राजा और प्रावधानों में बड़े बदलाव...

नए विधेयक में छल, दबाव या प्रलोभन से धर्मांतरण कराने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकेगा, जबकि पहले यह दायरा केवल खून के रिशतों तक सीमित था। सामान्य धर्म परिवर्तन के मामलों में जेल की सजा को बढ़ाकर तीन से दस वर्ष कर दिया गया है, जो पहले दो से सात वर्ष थी। इसके अलावा जिलाधिकारी को गैंगस्टर एक्ट की रजर्ज पर संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। विवाह का झंझा देकर, हमला, भ्रष्टाचर, नाबालिगों की तस्करी, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के जरिए धर्मांतरण कराने पर न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में दोनोंपक्ष पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

